हरियाणा के चुनाव की सबसे उल्लेखनीय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को इसका लाभ मिला भी था (उन लोगों की बात छोड़िए, जो यह कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के वोट भाजपा के पक्ष में चले गए थे)।

लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को जो ताकत मिली थी, उसे पार्टी ने कैसे खो दिया तथा हरियाणा में भाजपा के प्रभाव की वृद्धि को उसने कैसे अनदेखा कर दिया–यही इस चुनाव की असली कहानी है तथा आगे के कुछ बिन्दुओं में इसी का विश्लेषण किया गया है। दरअसल, भाजपा ने एक विधानसभा चुनाव को 90 चुनावों में बाँट लिया था तथा हर सीट का चुनाव एक पृथक चुनाव की तरह लड़ा था।

आम तौर से किसी भी विधानसभा चुनाव में, जहाँ भाजपा जीतती हैं, 60–65 प्रतिशत सीटों पर राज्य/राष्ट्र स्तरीय मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तथा शेष 35–40 प्रतिशत सीटों पर क्षेत्र स्तर, स्थानीय तथा ठेठ स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

इस बार हरियाणा में, यह अनुपात उलट दिया गया था। सत्तर प्रतिशत सीटों पर चुनाव क्षेत्र के मुद्दों पर फोकस किया गया था तथा शेष सीटों पर राज्य–राष्ट्र स्तर के मुद्दे प्रमुख रखे गए थे। "पर्ची–खर्ची" सम्बन्धी लेख राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों का रूप ले रहे थे तथा कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे थे। लेकिन, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में, उस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पूरे जोर–शोर से सामने लाये जा रहे थे। इसके अलावा, राज्य–स्तरीय मुद्दों को स्थानीय रंग दे दिया गया था – "पर्ची–खर्ची से (चुनाव क्षेत्र का नाम) के युवाओं को रोज़गार से वंचित रखने की कांग्रेस (हूड्डा) की साजिश"। इस पहलू से, दोनों पार्टियों की नीति–क्रियान्वयन क्षमताओं के बीच के अन्तर पर जोर दिया गया।

अगला उदाहरण यह दर्शाता है कि अति–स्थानीयता स्वयं भाजपा के खिलाफ भी चली गई। दक्षिणी हरियाणा के गुड़गाँव क्षेत्र की अटेली सीट पर भाजपा की आरती सिंह राव केवल 3000 वोटों के अन्तर से ही जीत सकीं।

आरती राव केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्री राव इन्द्रजीत सिंह की बेटी हैं। इन्द्रजीत सिंह हरियाणा के वरिष्ठतम यादव नेता माने जाते हैं तथा राज्य के दक्षिणी हिस्से की अहीरवाल बैल्ट पर उनका पूरा प्रभुत्व है। हरियाणा के चुनाव परिणामों की परम्परागत समझ यह कहती है कि यादव (तथा अन्य गैर–जाट समुदाय) इसलिए भाजपा के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कांग्रेस शासन में जाटों के दबदबे की तुरंत वापसी हो जाती है। अगर परिणामों के पीछे केवल या प्राथमिक रूप से यही कारण होता, तो अटेली की भाजपा प्रत्याशी जीत का अन्तर राज्य में उसकी जीत के सबसे बड़े अन्तरों में से एक होता। हरियाणा की अन्दरुनी कहानी यह है कि जाटों की एकजुटता के जवाब में अन्य समुदायों की एकजुटता यदा–कदा ही परिणामों का कारण बनती है। जहाँ यादवों की एकजुटता से दक्षिण हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर भी भाजपा को मदद मिली, वहाँ आरती राव जैसी प्रत्याशी भी मामूली अन्तर से जीतीं, क्योंकि अटेली सीट के चुनाव को भी, अन्य सीटों की तरह, स्थानीय रंग दे दिया गया था।

एक खास बात और, राव को यह 3000 वोटों की जीत भी बसपा प्रत्याशी पर मिली, कांग्रेस प्रत्याशी पर नहीं। ज्ञातव्य है कि बसपा आज एक ऐसी पार्टी है, जिसे हरियाणा तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता का दावेदार नहीं माना जाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि हरियाणा में चुनाव के स्थानीयकरण का लाभ भाजपा को मिला है।

अति स्थानीयता के बिन्दु के अलावा, भाजपा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "वोट–कटर्स" का प्रबन्धन भी किया था। विधानसभा क्षेत्र–स्तर पर, सीट के हिसाब से, भाजपा अपने उम्मीदवार को ही आगे नहीं बढ़ा रही थी, वह अप्रत्यक्ष रूप से, वह "वोट–कटर्स" को भी आगे बढ़ा रही थी।

ये वोट–कटर अन्य पार्टियों के थे या निर्दलीय थे, जिन्हें भाजपा ने ही रणनैतिक रूप से आगे बढ़ाया था। कुछ वोट उस क्षेत्र में थे।

पार्टी संगठन ने सोचे–समझे तरीके से बगावती/निर्दलीय प्रत्याशियों पर फोकस किया था। सीमित प्रभाव वाले प्रत्याशियों से लेकर, समर्थकों की अच्छी खासी संख्या वाले नेताओं तक, हर प्रत्याशी पर भाजपा ने प्यार लुटाया था तथा अपनी योजनानुसार उसे हैंडल किया था।

द. कोरिया की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पत्रिका में कई कविताओं के प्रकाशन के साथ की। उन्होंने गद्य की शुरुआत 1995 में लघु कहानी संग्रह "लव ऑफ येओसु" के साथ की। इसके बाद उनके उपन्यास और लघु कथाएँ प्रकाशित की गयी। कांग को 2016 में उनकी कृति "द वेजिटेरियन" के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

स्विमिंग पूल के अश्लील वीडियो वाले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेवा में लेने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह याचिकाकर्ता को जारी की गई चार्जशीट के आधार पर जांच कर सकता है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ तभी कार्रवाई की जा सकती है, जब कर्मचारी को सुनवाई का मौका मिले और उस पर लगाए गए आरोप साबित हो जाएं। कर्मचारी के खिलाफ नियमित जांच से यह कहते हुए छूट नहीं दी जा सकती कि उसके कृत्य से समाज और विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि इस दलील को स्वीकार कर लिया जाए तो ए.सी.बी. केस में रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले कर्मचारी भी तो विभाग की छवि खराब करते हैं, जबकि उन मामलों में सरकार आपराधिक प्रकरण के निपटारे का इंतजार करती है। नियमित जांच से छूट देते हुए कर्मचारी को बर्खास्त करने का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होता है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता और एक महिला पुलिसकर्मी का स्विमिंग पूल का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिला का छह साल का बेटा भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक अक्टूबर, 2021 को याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया और जांच व सुनवाई का मौका दिए बिना, उसी दिन उसे बर्खास्त कर दिया, जबकि बिना जांच बर्खास्त करने का प्रावधान उन मामलों में ही लागू होता है, जिनमें जांच करना ही संभव नहीं हो। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा था और जांच की जा सकती थी।

सैमसंग के चेन्नई प्लांट में हड़ताल,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का था, जिसे मैनेजमैंट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने हड़ताली मजदूरों पर बल प्रयोग किया। बुधवार को सुबह राज्य पुलिस ने यूनियन के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारियों के टैंट हटा दिए। सैंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) से संबंधित एक हजार श्रमिकों ने 9 सितम्बर को अपनी नई बनी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने और कामकाज के हालात बेहतर बनाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी थी। कड़ी पुलिस कार्यवाही भी तब ही हुई, जब द्रमुक के सहयोगी दलों के नेता बुधवार को प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे। इनमें कांग्रेस, माकपा, एम.डी.एम.के. भाकपा और वी.सी.के. दलों के नेता शामिल थे। राजनैतिक विश्लेषकों ने मजदूरों के मुद्दे पर उभरे मतभेद पर तुरंत ध्यान दिया और वे हैरान है कि क्या गठबंधन में और बड़े मतभेद उभर सकते हैं।

गत माह जब विरोध प्रदर्शन शुरु हुआ था तब स्टालिन अमेरिका में थे। द्रमुक ने हमेशा बिज़नेस फ्रैंडली छवि पेश की है और इस वजह से ही राज्य में कई बिज़नैस प्रोजैक्ट आए और तमिलनाडु देश का निर्माण केन्द्र बन गया। वामपंथी दलों से जुड़े श्रमिक संगठनों की हड़ताल ऐसे समय पर हुई, जब मुख्यमंत्री निवेश के लिए अमेरिका गए थे। द्रमुक ने इसे विश्वासघात माना। ज्ञातव्य है कि वामपंथी दल कई दशकों से द्रमुक का समर्थन कर रहे हैं।

कंपनी, सैमसंग इण्डिया, जो इस विवाद के केन्द्र में है, ट्रेड यूनियन के साथ लड़ना नहीं चाहती है, इसके बजाय सीधे श्रमिकों से बातचीत करना चाहती है। सैमसंग इण्डिया ने सन् 2007 में प्लांट शुरु किया था और कंपनी में हड़ताल की यह पहली घटना है तथा इसने कंपनी के उत्पादन पर प्रभाव डाला है। ट्रेड यूनियन के सूत्रों का आरोप है कि सरकार ने हाल ही में गठित ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं होने दिया। इस निर्णय को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास करती रही है और इस संदर्भ में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें तीन मंत्रियों ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार, कंपनी वेतन बढ़ाने तथा अन्य लाभ देने के लिए राजी हो गई और सरकार ने दावा किया कि समझौता हो गया है। लेकिन, ट्रेड यूनियन तथा कर्मचारियों ने यह कहते हुए इस दावे को रिजैक्ट कर दिया कि उनकी तरफ से जिन लोगों ने मीटिंग में भाग लिया था वो वास्तव में उनका (ट्रेड यूनियन व कर्मचारियों) प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते हैं।

कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने तो यह घोषणा भी की थी कि इस मुद्दे का एक प्रस्ताव भी है– "सैमसंग इंडिया ने आज अपनी चेन्नई फैक्टरी की मजदूर समिति के साथ एक "मैमोरेण्डम ऑफ अग्रीमैंट" पर हस्ताक्षर किए---- अवैध हड़ताल खत्म करने के तमिलनाडु सरकार के प्रयासों से हम अवगत हैं तथा निरंतर समर्थन के लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं।"

लेकिन, कर्मचारियों को यह मंजूर नहीं था। सीटू अध्यक्ष, ए. सौंदरराजन ने कहा, सोमवार को जिन कर्मचारियों ने मैमोरेण्डम पर हस्ताक्षर किए, वो हड़ताल का हिस्सा नहीं थे। सौंदरराजन ने घोषणा की कि हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की मांग स्वीकार नहीं की गई है।

उन्होंने फिर दोहराया कि जब तक यूनियन को मान्यता देने की मांग नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगी। बुधवार सुबह हिरासत में लिए गए लोगों में सीटू नेता सौंदरराजन व मुतुकुमार भी शामिल थे। सीटू ने हड़ताल को बढ़ाने तथा और तेज करने का निर्णय लिया है और 21 अक्टूबर को राज्य भर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आ ान किया है।

अमेरिका के पूर्ण समर्थन के बावजूद इज़रायल अपना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हमले का निर्णायक रुप से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्मीन समाचार एजेंसी ने ईरानी शस्त्र बलों के एक जानकार सूत्र के हवाले से कहा कि देश ने इज़रायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में कई लक्ष्यों की पहचान की है और इज़रायल जिस तरह के हमले करेगा उसके आधार पर उनका जवाब दिया जाएगा। ईरान की जवाबी योजना एकदम तैयार है और जैसे ही इज़रायल कोई एक्शन लेगा इस योजना को लागू कर दिया जाएगा।

इज़रायल किस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करता है उसके आधार पर ही ईरान कार्यवाही करेगा। हालांकि चर्चा है कि इज़रायल द्वारा ईरान के परमाणु केन्द्रों और तेल के कुओं को निशाना बनया जा सकता है। ईरान के पास कई प्रकार की जवाबी रणनीतियाँ हैं। वह लक्ष्य भेदने वाले हमले भी कर सकता है। हाल ही में दिखाई अपनी ताकत में ईरान ने "ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस–द्वितीय" शुरू किया। जिसके तहत इज़रायल के सैन्य अड्डों एवं गुप्तचर केन्द्रों पर 200 मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने यह कार्यवाही इज़रायल द्वारा की गई उस कार्यवाही के जवाब में की थी जिसमें हमास का नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह और ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का सीनियर कमांडर मारा गया था।

इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इज़रायल के कब्जे वाले क्षेत्र पर 300 मिसाइलें दागी थीं व ड्रोन हमले किए थे। उस हमले को "ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस" नाम दिया गया था। यह कार्यवाही इज़रायल द्वारा सीरिया पर किए गए हमले के जवाब में की थी। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इज़रायल से अपना बचाव करने का अधिकार है और वो किसी भी हमले का करारा जवाब देगा लेकिन तेहरान ने चेतावनी दी है कि इज़रायल ने अगर कोई हमला किया तो उस पर इससे भी भारी कार्यवाही की जाएगी।

अटकले हैं कि ईरान इज़रायल के परमाणु केन्द्रों, ऊर्जा संयंत्रों और एयर बेस पर हायपरसॉनिक मिसाइल हमला कर सकता है। अगर यह सच है तो दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसका क्षेत्र पर, दुनिया पर भारी प्रभाव पड़ेगा। हायपरसॉनिक मिसाइलें अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती हैं।

ईरान के हालिया हमले के जवाब में इज़रायल कथित रूप से ईरान के परमाणु संयंत्रों, तेल के कुओं, ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी में है। ईरान के सैन्य क्षमता को नियंत्रित करने और क्षेत्रीय आंतकी संगठनों को फंड देने की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए यह हमला किया जाएगा।

हालांकि इज़रायल ने अभी ऐसे किसी हमले की पुष्टि नहीं की है। सैन्य व राजनैतिक पर्यवक्षक हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। इज़रायल की सामरिक ताकत उसकी अत्याधुनिक वायुसेना और सैन्य टैक्नॉलजी में है जो ईरान को उसके एयर डिफैंस के बाद भी अंदर तक नुकसान पहुंचा सकती है।

लेकिन राष्ट्रपति बाइडन सहित, अमेरिकन अधिकारियों ने इजरायल से यह कह दिया बताते हैं कि वह ईरान के तेल–इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले के वैकल्पिक तरीके तलाश करे। अमेरिका इस बात को लेकर चिन्तित है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा हमला बोलने से, युद्ध की स्थिति नाटकीय–वृद्धि हो सकती है तथा हिजबुल्लाह जैसे ईरान के क्षेत्रीय मित्र भी उसके साथ खुलकर आ सकते हैं तथा लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है, जिसे काबू में लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने के बजाय, अमेरिका, ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने के लिए, कूटनीति उपायों तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के साधनों का उपयोग करना बेहतर समझता है तथा इसके साथ ही, अमेरिका इज़रायली सेनाओं को सहारा देने के लिए उसे सैन्य–सहयोग देते रहना चाहता है।

इन चिन्ताओं के बावजूद, वॉशिंगटन इज़रायल की सुरक्षा–जरूरतों में सहयोग करते रहने के प्रतिबद्ध है तथा वह इज़रायली गुप्तचरों तथा सैन्य–नियोजकों को सहयोग–सहायता देने रहना जारी रखेगा।

लेकिन, इस प्रकार के दावों की विश्वसनीयता को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा भू–राजनैतिक प्रतिस्पर्धाओं के संदर्भ में, उत्तेजनापूर्ण तथा बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का उभरना सम्भव है। ईरान और इज़रायल ऐसे विभिन्न रणनैतिक, सैद्धान्तिक तथा रक्षा सम्बन्धी मुद्दों को लेकर लम्बे समय से आमने–सामने हैं, और अक्सर वे एक–दूसरे को धमकी देते हैं तथा कभी–कभी सैन्य टकराव भी होता है।

अपराधी या तो अपराध छोड़ दें...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुए नशे के विरूद्ध कार्रवाई करे। हमारा लक्ष्य है कि मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति से युवाओं को बचाया जाए। शर्मा ने जेलों में मोबाइल फोन संबंधी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पेपरलीक प्रकरणों में एस.ओ.जी. द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में एसओजी की कार्रवाई की वाह–वाही हो रही है।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार विभाग, अभियोजन, गृहरक्षा विभाग की बजटीय घोषणाओं की समीक्षा की तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती एजेन्सियाँ भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एकसाथ आयोजित करने पर भी विचार करें। समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केन्द्र विकसित किए जाएं तथा वहां सी.सी.टी.वी. सहित अन्य सुरक्षा इंतेजाम किए जाएं, ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हों।

सर्च ऑपरेशन से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी उसका शिकार बनेंगे। नान्देशमा के कैलाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में पैंथर का मूवमैंट बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब एक महीने में गोगुंदा इलाके में पैंथर 9 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इतने लोगों का शिकार किसी एक पैंथर ने किया है, या इनकी संख्या एक से ज्यादा है। वन विभाग से लेकर पुलिस की टीमें सर्च में जुटी हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है।

सी.एम. ने प्रधानमंत्री का आभार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 1 लाख 78 हजार 173 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें अक्टूबर, 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा, अतिरिक्त अग्रिम किस्त भी शामिल है। हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क तंत्र के विकास के लिए 4 हजार 406 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक–राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333–34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744–2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294–2410146, अजमेर कार्यालय:–राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145–2624665, जालोर कार्यालय :– जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973–226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :– जी –1–201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469–230600 चूरू कार्यालय : एच–150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562–256908